भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **1953**

दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 / 18 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कृषि उड़ान 2.0 योजना

1953. श्री अर्जुन लाल मीणा:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री पी.पी.चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उड़ान 2.0 योजना के अंतर्गत शामिल किए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के जिलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है तथा इसमें किन विमान कंपनियों ने हिस्सा लिया है;
(ग) ई-कुशल के विकास की समय-सीमा क्या है और पोर्टल पर डेटा डालने का क्या प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) पोर्टल के साथ इस योजना के अंतर्गत डेटा के डिजिटलीकरण और एकीकरण के प्रस्ताव की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) , विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): कृषि उड़ान 2.0 योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओड़ीशा तथा राजस्थान के निम्नलिखित हवाईअड्डों को शामिल किया गया है,

उत्तर प्रदेश: आगरा, गोरखपुर, हिंडन, कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी।
मध्य प्रदेश: इंदौर
ओड़ीशा: कोई नहीं
राजस्थान: जैसलमर एवं जोधपुर।

(ख): कृषि उड़ान विभिन्न योजनाओं को जोड़ने वाली एक योजना है, जिसमें आठ मंत्रालय/विभाग, नामतः नागर विमानन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), कृषि-उत्पाद के परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने के क्रम में अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ लेंगे। नागर विमानन मंत्रालय कृषि उड़ान 2.0 के अंतर्गत चुनिन्दा हवाईअड्डों में कृषि-उत्पाद ले जाने वाली कार्गो उड़ानों के माध्यम से फ्रेटर तथा यात्रियों को प्रोत्साहन दे रहा है। इस योजना के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं है।

(ग) से (ड.): ई-कुशल (सतत समग्र कृषि-लॉजिस्टिक्स के लिए कृषि उड़ान) संगत जानकारी प्रदान करने वाला एकल मंच होगा। यह ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के लिए ई-कुशल के एकीकरण के लिए, योजना के समन्वय, निगरानी एवं मूल्यांकन में भी सहायता करेगा। ई-कुशल का क्रियान्वयन, हितधारकों के सहयोग के साथ, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

*****